

:: प्रधान आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए डी. द्वारा :-

अपील / फाइल संख्या /

मुल आदेश मं /

दिनांक /

Appeal / File No.

O.I.O. No.

Date:

V2/48/BVR/2019

03/Supdt/Alang-4/BVR-2/2018-19

31.07.2018

अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-013-2020

आदेश का दिनांक /

जारी करने की तारीख /

20.03.2020

Date of Order:

17.03.2020

Date of issue:

गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित / Passed by Shri Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ नेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / भावनगर / गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot/Bhavnagar/Gandhidham

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellants & Respondent :-

M/s Shri Saibaba Ispat (I) Pvt. Ltd., Plot No. 135, SBY SOSYO, Bhavnagar, Gujarat.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way. सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं

(A) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६ को की जानी चाहिए ।/ To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भूगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के माथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ः/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र s.r.-s में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति माथ में संलग्न करें (उनमें मे एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,व्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न अपकेर्क निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के महायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित ᢏारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । **`क्षांदेंशो**(स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be dertified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty कर्रात अंदेंपांक क्रि. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not rင့်မေါ်ာ်မှု Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in The form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

विच अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) पूर (2A) के अस्टिट दर्ज की सुवी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेनी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित डोकी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ मेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (नेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारः 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते ममय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब नांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)

(i)

- मेनवेट जमा की ली गई गलत राजि (ii)
- मेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं· 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- amount determined under Section 11 D; (i)
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules (iii)
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014. भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
- Revision application to Government of India: (C) इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुन्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, विच मंत्रात्य, राजस्व विभाग, बौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue. 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

बादे माल के किमी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रह माल क विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए विना भारत के बाहर, नेपाल या भुटान को माल नियात किया गया है। /

(iii)

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जा ड्यूटी कड़ीट इस आधीन्यम एव इसके विभिन्न प्रावधाना के तहत मान्य की गई है और एस आदेश जो अयुक्त (अपील) के द्वारा विन अधिनियम (न॰ 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित (iv)

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. उपरोक्त आवंदन की दो प्रतिया प्रपत्र मंख्या EA-8 में, जा की कन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 साह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवंदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया संलग्न की जानी चाहिए।

(v) साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. पुनराक्षण आवदन के साथ निम्नालेखित निधारित शुल्क का अदायगा की जानी चाहिए। जहाँ मंलग्र रकम एक लाख रूपये यो उससे कम हो तो रूपये 200% का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये

(vi) 1000 -/ का भगतान किया जाए ।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक सूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य में बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / lin case, (D) if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसुची-! के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का ^अन्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a Court fice stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

भीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मेवाकर अपीलीय त्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संवन्धित मामलों को अम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /

Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs. Excise

पार्थिय में श्रीति Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

अर्थिय में श्रीति Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

अर्थितियेय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने में मंदियित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलाथी विभागीय वेबसाइट अर्थितिय प्राधिकारी के लिए, अपीलाथी विभागीय वेबसाइट अर्थितिय अर्थितिय प्राधिकारीय के लिए, अपीलाथी विभागीय वेबसाइट अर्थितिय अर्थित अर्थितिय अर्थितिय

For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

(i)

(ii)

ORDER-IN-APPEAL

M/s Shree Saibaba Ispat (India) Pvt Ltd, Bhavnagar [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/48/BVR/2019 against Order-in-Original No. 3/Supdt/Alang-4/BVR-2/2018-19 dated 30.7.2018 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Superintendent, Central Goods and Service Tax, Alang-4 Range, Bhavnagar-2 Division, Bhavnagar [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

- 2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. CGST/Alang-4/SCN-5/Saibaba-135/17-18 dated 29.11.2017 was issued to the appellant for non filing of ER-1 Returns. The adjudicating authority imposed penalty of Rs 60,000/- and Rs. 5,000/- vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.
- 3. I find that the Appellant vide letter dated 10.1.2020 informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and requested to keep their appeal under abeyance. I find that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 25.2.2020 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019, as conveyed by CGST, Bhavnagar vide email dated 13.3.2020.
- 4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:
 - "(6) Where the declarant has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn."

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

(GOPI NATH)
Commissioner(Appeals)

<u>Attested</u>

(V)>

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

By R.P.A.D.

To,

M/s Shree Saibaba Ispat (India) Pvt Ltd. Plot No. 135, SBY Sosyo, District Bhavnagar. सेवा में.

मे॰ श्री साईबाबा इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट न॰ 135, एसबीवाई सोसयो,

जिल्ला भावनगर।

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर-2 मण्डल, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेत्।
 - 4) गार्ड फ़ाइल।

